www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240
आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 पुलिस-प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती... | 3 पत्रकार एसोसिएशन प्रयागराज की बैठक मीडिया... | 4 हरविन्द्र कल्याण ने घरौंडा हलके को दी सवा...

वर्षः 9 | अंकः 265 | दिल्ली, शनिवार, 19 जुलाई 2025 | पृष्ठ संख्याः 4 | मूल्यः 1 रुपया

मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश

रजनीश पुष्कर, ब्यूरो चीफ संजना भारती

मोतिहारी। मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी विकास परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के विकास के लिये किये गये कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश जी की सरकार ने बिहार के लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरी दी है। बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने का भी निश्चय किया है। नीतीश जी ने जीविका दीदी योजना चलाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिया है। नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया है, यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जा रहा है। इनके इस फैसले से वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा बहनों को काफी राहत मिलेगी। नीतीश जी नई उम्मीदों की रौशनी वाला बिहार बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।

■ प्रधानमंत्री ने 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ

जनसभा को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मोतिहारी पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही यहां उपस्थित बिहार के राज्यपाल महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी पधारे हैं। यहां 8 रेल परियोजनाओं, 7 सड़क परियोजनाओं एवं 3 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही चार ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थियों को राशि दी जा रही है और इन सबकी कुल लागत 7217 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आप सब जानते हैं पहले क्या हाल था, पहले की सरकार में कोई काम नहीं होता था। 24 नवंबर, 2005 को यहां एन०डीए० की सरकार बनी तब से हमलोग विकास का काम कर रहे हैं। 20 साल से हमलोग बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। पहले बिहार का बजट मात्र 24 हजार करोड़ रुपया हुआ करता था। अब यह बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। लोगों के हित में काम किया जा रहा है।

कार्यक्रम की शुरूआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुली जीप में जनसभा स्थल पर लगे पंडाल में उमड़े जनसैलाब के बीच से मुख्य मंच की तरफ जाते हुए समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया।

गीता स्थली ज्योतिसर बनेगा विश्व का भव्य और यादगार ऐतिहासिक पर्यटन स्थलः नायब सिंह सैनी

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत को मिली मजबूती-सीएम

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गीता स्थली ज्योतिसर विश्व का भव्य, यादगार और ऐतिहासिक स्थल बनेगा। इस गीता स्थली को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से करीब 250 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जा रहा है। यहां पर ज्योतिसर अनुभव केंद्र में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को कुरुक्षेत्र के इतिहास के जीवंत दर्शन होंगे।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जिला कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र का दौरा कर स्वागत कक्ष, महाकाव्य सृजन कक्ष, प्राचीन महाभारत, कुरुवंशावली, गीता श्लोक, कृष्ण भूमिका, दशव अवतार सहित अन्य कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी उपस्थित रहे। पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती कला रामचंद्रन ने ज्योतिसर अनुभव केंद्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ज्योतिसर अनुभव केंद्र के साथ-साथ अन्य कक्षों के छोटे-छोटे निर्माण कार्य को पूरा करने के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि ज्योतिसर अनुभव केंद्र को पर्यटकों के लिए खोला जा सके। मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर अनुभव केंद्र को विश्व दर्शनीय स्थल बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि तमाम विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाए ताकि ज्योतिसर अनुभव केन्द्र में पर्यटक महाभारत और कुरुक्षेत्र के इतिहास के दर्शन कर सकें। इसके अलावा, मुख्यमंत्री गीता ज्ञान संस्थानम में पहुंचे और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद से बातचीत की है।

इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से गीता के उपदेश दिए। इस पावन धरा के इतिहास को जहन में रखते हुए सरकार की तरफ से ज्योतिसर में विकास कार्यों को तेज गति के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती मिली है। इस देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए सरकार की तरफ से ज्योतिसर में महाभारत थीम पर आधारित प्रोजेक्ट पर करीब 250 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। इस ज्योतिसर गीता स्थली को विश्व का सबसे दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल बनाया जा रहा है।

सीआईएल ने छत्तीसगढ़ में ईएमआरएस को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रु देने की प्रतिबद्धता जताई

■ आदिवासी छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

नई दिल्ली। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए साझेदारी की है। सीआईएल अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत छत्तीसगढ़ में 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को सहयोग प्रदान करेगा, जिससे 28,000 से अधिक आदिवासी छात्र लाभान्वित होंगे।

भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ईएमआरएस की स्थापना करता है ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकें। ईएमआरएस उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के अलावा, उनके पोषण, समग्र स्वास्थ्य और विकास का भी ध्यान रखता है। आज, देश भर में 479 ईएमआरएस कार्यरत हैं। सीआईएल ने घोषणा की है कि वह जनजातीय कार्य मंत्रालय को उसकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के तहत सहयोग देगा और निम्नलिखित कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं:

कंप्यूटर लैब स्थापित करके डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना; लगभग 3200 कंप्यूटर और 300 टैबलेट खरीदे जाएँगे; स्कूलों और छात्रावासों में लगभग 1200 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और 1200 इंसिनरेटर स्थापित करके छात्राओं की स्वास्थ्य स्वच्छता;छात्रों के लिए व्यापक मार्गदर्शन; औरछात्रों के लिए आवासीय उद्यमिता बूट कैंप (आईआईटी/आईआईएम/एनआईटी में).

इस व्यापक हस्तक्षेप के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय और सीआईएल ईएमआरएस में आधुनिक और नवीन शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने और समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। इस सहयोग का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा, करियर की तैयारी और उद्यमशीलता की मानसिकता के माध्यम से आदिवासी युवाओं के लिए शैक्षिक अंतराल को पाटना और नए रास्ते खोलना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के लिए समान और समावेशी शैक्षिक अवसर सृजित करने के सरकार के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है। यह परियोजना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी, जो मंत्रालय के अंतर्गत एक सेक्शन 8 कंपनी है।

दिल्ली को नशा मुक्त बनाने में महिलाओं की सहभागिता जरूरीः रविन्द्र इंद्राज

■ वालंटियर बनकर परिवार और समाज को नशामुक्त बनाने में दे सकती हैं अहम योगदान

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने शुक्रवार को उत्तर दिल्ली जिले में नशामुक्ति अभियान की प्रगति और रणनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नशे पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है, इसकी रोकथाम। महिलाओं को नशामुक्ति अभियान से जोड़कर परिवार और समुदाय स्तर पर जागरूकता को नई दिशा दी जा सकती है। जे जे कॉलोनी, झुग्गियों और क्लस्टरों में महिलाओं को जागरूक करें। महिलायें वालंटियर बनकर परिवार और समाज को नशामुक्त बनाने में अहम योगदान दे सकती हैं।

श्री रविन्द्र इंद्राज ने कहा कि नशे पर नियंत्रण के लिए केवल कानून का ही नहीं, समाज का सहयोग भी आवश्यक है, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को नशे के आदी होने के लक्षणों, हेल्प लाइन नंबर, डिएडिक्शन सेंटर की जानकारी देकर परिवार और पड़ोस में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करें। श्री रविन्द्र इंद्राज ने बताया कि उन्होंने नशे के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बीट अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। साथ ही, पुलिस से चयनित डार्क स्पॉट्स की सूची साझा करने और वहां सघन निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि जागरूकता अभियानों को प्रभावी ढंग से चलाया जाए। उन्होंने मेडिकल स्टोर्स और अन्य दुकानों पर नशीले उत्पादों की बिक्री पर विशेष निगरानी रखने और सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्कों व टॉयलेट्स में नशे के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने को कहा।

समाज कल्याण मंत्री ने छात्रों को नशे से बचाने हेतु स्कूल-कॉलेज परिसरों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और इसकी सख्ती से निगरानी कराने के निर्देश दिए।

समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत दिल्ली को नशामुक्त बनाने और पुनर्वास सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभागों के बीच समन्वय को और अधिक मजबूत किया जाए। साथ ही, निजी संगठनों के अनुभव, संसाधनों और मानवशक्ति का उपयोग किया जाए।

श्री रविन्द्र इंद्राज ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों से अपने परिसरों में नशा मुक्ति क्लब बनाने और ड्रग फ्री कैंपस घोषित करने का आग्रह किया गया है। बैठक में डीएम एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, समाज कल्याण विभाग और इस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ ने अभियान की प्रगति की जानकारी दी।

श्री रविन्द्र इंद्राज ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग फ्री दिल्ली-ड्रग फ्री भारत लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभागों को समन्वय बनाकर अपना योगदान देने के आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सभी विभागों और संगठनों ने अपने अनुभव साझा किए और विकसित व नशामुक्त दिल्ली के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संयुक्त प्रयासों का संकल्प लिया।

■ संक्षिप्त समाचार

गैर-बीजेपी राज्यों में पेट्रोल-डीजल 7 से 8 रुपये महंगा

पश्चिम बंगाल (एजेन्सी)। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने दोहराया कि गैर-भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भाजपा शासित राज्यों से अधिक हैं। दुर्गापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर बोलते हुए, मंत्री पुरी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 7-8 रुपये प्रति लीटर कम हैं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ईंधन की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया। नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2024 में, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उपकर में क्रमशः 13 रुपये और 16 रुपये की कटौती की। मंत्री पुरी ने किसी राज्य या उनके नेताओं का नाम लिए बिना कहा, "इसके अलावा, हमारे भाजपा शासित राज्यों ने भी ईंधन पर वैट कम कर दिया है। भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें गैर-भाजपा शासित राज्यों की तुलना में 7-8 रुपये प्रति लीटर कम हैं।"

स्वर्ण मंदिर बम धमकी, श्री दरबार साहब को बम से उड़ाने की धमकी देनेवाला गिरफ्तार

अमृतसर (एजेन्सी)। पुलिस ने बताया कि पंजाब के अमृतसर स्थित सिखों के पवित्र तीर्थस्थल स्वर्ण मंदिर को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की पांच धमकियों के सिलसिले में हरियाणा के फरीदाबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। आरोपी शुभम दुबे (24) को 14 जुलाई को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) को भेजे गए पहले धमकी भरे ई-मेल के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दुबे का लैपटॉप और फोन जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि दुबे के पास बी.टेक की डिग्री है और वह कई कंपनियों में काम कर चुका है। कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि दुबे का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। भुल्लर के अनुसार, दुबे को पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट और केंद्रीय खुफि या एजेंसियों की मदद से पकड़ा गया। हालाँकि, उसे औपचारिक रूप से गिरफ़्तार नहीं किया गया है। भुल्लर ने इस गिरफ्तारी को आंशिक सफलता बताते हुए कहा कि जाँच जारी है और आने वाले दिनों में और प्रगति की उम्मीद है।

लालू प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने से न्यायालय का इनकार

नई दिल्ली (एजेन्सी)। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआई के जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा। शीर्ष अदालत ने मामले में यादव को निचली अदालत में पेशी से छूट भी प्रदान की। गत 29 मई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। उच्च न्यायालय ने एजेंसी की प्राथमिकी रद्द करने की यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और सुनवाई 12 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

मंत्री कपिल मिश्रा ने किया प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा

देश की राजनीति, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता को दर्शाते पर्यटक स्थल दिल्ली की पहचान हैंः कपिल मिश्रा

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज तीन मूर्ति मार्ग स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रसिद्ध गायक एवं संगीत निर्देशक हिमेश रेशमिया भी उपस्थित रहे। भ्रमण के दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने संग्रहालय की विभिन्न तकनीकी विशेषताओं और गैलरियों का गहन अवलोकन किया।

प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित 14 अत्याधुनिक गैलरियां हैं, जो भारत के राजनैतिक इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। संग्रहालय की विशेषताओं में 6D हेलिकॉप्टर राइड, इंटरैक्टिव जोन, वर्चुअल फोटो सेशन, हैंडराइटिंग रोबोट, टाइम मशीन, 3D नेशनल एम्बलम और काइनेटिक एलईडी लाइट्स से युक्त राष्ट्रीय ध्वज जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं।

इस अवसर पर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय न केवल हमारे देश के इतिहास को जीवंत करता है बल्कि यह युवाओं को प्रेरणा देने का भी एक माध्यम है। यह भारत के महान नेताओं की यात्राओं और योगदान का सजीव दस्तावेज है। हर भारतीय को यहां आकर भारत के गौरवशाली नेतृत्व की झलक अवश्य देखनी चाहिए।

इसके साथ ही मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि कर्तव्य पथ, भारत मंडपम, प्रधानमंत्री संग्रहालय, डॉ. अम्बेडकर स्मारक जैसे आधुनिक भारत की पहचान वाले पर्यटक स्थलों पर देशभर से लोग आएं। इसी क्रम में मशहूर गायक हिमेश रेशमिया के साथ दिल्ली के प्रमुख टूरिज्म स्मारक प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाना हुआ। देश की राजनीति, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता को दर्शाते ये नए पर्यटक स्थल दिल्ली की पहचान हैं। हिमेश के साथ प्रधानमंत्री संग्रहालय जाकर हमने इस अभियान की शुरूआत की है। आप सभी दिल्ली के इन पर्यटन स्थलों पर जरूर जाएं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इन प्रेरणादायी और तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय स्थलों का भ्रमण करें और भारत की राजनीतिक विरासत, नेतृत्व की यात्रा तथा सांस्कृतिक गरिमा को अनुभव करें।

दिल्ली में बारिश के कारण येलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली (एजेन्सी)। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के कई इलाकों में हुई बारिश के बाद, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया। अपने पूर्वानुमान में, मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले घंटों में दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। IMD के 'येलो अलर्ट' के अनुसार, मध्यम बारिश की संभावना है और इसके प्रति 'सतर्क' रहने की आवश्यकता है। 'येलो अलर्ट' का अर्थ निचले इलाकों में जलभराव की संभावना भी है। इस बीच, शुक्रवार को राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हुई, जिससे अजमेर, कोटा और पुष्कर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। मौसम विभाग के अनुसार, कोटा के सांगोद में सबसे ज्यादा 17 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में 11 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक और पाली में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर और नागौर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

सम्पादकीय

पंच परिवर्तन से बदल जाएगा समाज का चेहरा-मोहरा

इतिहास के चक्र में किसी सांस्कृतिक संगठन के सौ साल की यात्रा साधारण नहीं होती। यह यात्रा बीज से बिरवा और अंततः उसके वटवृक्ष में बदल जाने जैसी है। ऐसे में उस संगठन के भविष्य की यात्रा पर विमर्श होना बहुत स्वाभाविक है। स्वतंत्रता के अमृतकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संकल्प भविष्य के भारत की रचना में सहयोगी बन सकते हैं। अपने शताब्दी वर्ष में संघ ने पंच परिवर्तन का संकल्प लिया है। यह पंच परिवर्तन क्या है? इससे क्या होने वाला है? इसे भी जानना जरूरी है। संघ की मान्यता है कि व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब भारत की व्यवस्थाएं स्व पर आधारित हों। स्व आधारित तंत्र बनाना साधारण नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर देश के तमाम विचारक और राजनेता स्व की बात करते रहे, किंतु व्यवस्था ने उनके विचारों को अप्रासंगिक बना दिया। समाज परिवर्तन के बिना व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं, इसे भी सब मानते हैं। वैचारिक संभ्रम इसका बहुत बड़ा कारण है। हम आत्मविस्मृति के शिकार और आत्मदैन्य से घिरे हुए समाज हैं। गुलामी के लंबे कालखंड ने इस दैन्य को बहुत गहरा कर दिया है। इससे हम अपना मार्ग भटक गए। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, बाबा साहब आंबेडकर हमें वह रास्ता बताते हैं जिनपर चलकर हम अपनी कुरीतियों से मुक्त एक सक्षम, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी समाज बन सकते थे। किंतु अंग्रेजों के बाद सत्ता में आए नायकों ने सारा कुछ बिसरा दिया। उस आरंभिक समय में भी दीनदयाल उपाध्याय और डा. राममनोहर लोहिया जैसे नायक भारत की आत्मा में झांकने का प्रयास करते रहे किंतु सत्ता की राजनीति को वे विचार अनुकूल नहीं थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का जो संकल्प लिया है,वह भारत की चिति और उसकी स्मृति को जागृत करने का काम करेगा। राष्ट्रीय चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए 1. नागरिक कर्तव्य, 2. स्वदेशी, 3. पर्यावरण संरक्षण, 4. समरसता, 5. कुटुंब प्रबोधन जैसे पांच संकल्प ही पंच परिवर्तन के सूत्र हैं। इन विषयों में भारत की आत्मा को झकझोरकर जगाने और नया भारत बनाने का संकल्प झलकता है। किसी भी राष्ट्र और लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों की सहभागिता और कर्तव्यबोध से ही सार्थक होती है। एक जीवंत लोकतंत्र की गारंटी उसकी नागरिक चेतना ही है। कानूनों की अधिकता और उसे न मानने का मानस दोनों साथ-साथ चलते हैं। अपनी माटी के प्रति प्रेम, उत्कट राष्ट्रभक्ति ही सफल राष्ट्र का आधार है। जापान जैसे देशों का उदाहरण देते समय हमें देखना होगा कि क्या हमारी राष्ट्रीय चेतना और संवेदना वही है जो एक जापानी में है। आखिर क्या कारण है कि अपनी महान परंपराओं, ज्ञान परंपरा के बाद भी हम एक लापरवाह और कुछ मामलों में अराजक समाज में बदलते जा हैं। कानूनों को तोड़ना यहां फैशन है। यहां तक की हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और सड़कों पर रेड लाइट का उल्लंघन करने से भी बाज नहीं आते। ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, किंतु हैं बहुत बड़ी। चुनावों में शत प्रतिशत मताधिकार तो दूर का सपना है। बहुत शिक्षित शहरों में वोटिंग 50 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पाती। ये सूचनाएं बताती हैं कि हमें अभी जागरूक नागरिक या सजग भारतीय होना शेष है।कानूनों का पालन, कर का समय पर भुगतान, सामाजिक और सामुदायिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा जरूरी है। एक शानदार समाज की पहचान है कि वह अपने परिवेश को न सिर्फ स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करता है बल्कि अपने प्रयासों से अन्यों को भी प्रेरित करता है। देखा जाता है कि हममें अधिकार बोध बहुत है किंतु कर्तव्यबोध कई बार कम होता है। जबकि संविधान हमें मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी सीख देता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें नागरिकता और सामाजिक आचरण का पाठ पढ़ाते हैं। सवाल यह है कि हम उन्हें अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं। पंचपरिवर्तन का दूसरा सूत्र है स्वदेशी। स्वदेशी सिर्फ आत्मनिर्भरता का मामला नहीं है यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी विषय है। अपनी जमीन पर खड़े रहकर विकास की यात्रा ही स्वदेशी का मूलमंत्र है। विनोबा जी कहते थे- स्वदेशी का अर्थ है आत्मनिर्भरता और अहिंसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसे सादगी से भी जोड़ता है। जिसके मायने हैं मितव्ययिता से जियो, कंजूसी से नहीं। स्वदेशी का सोच बहुत व्यापक है। परिवारों में भाषा, वेशभूषा, भवन, भ्रमण, भजन और भोजन ये छः चीजें हमारी ही होनी चाहिए। हम विदेशी भाषा, बोलें, दुनिया के साथ संवाद करें। किंतु अपने परिवारों अपनी मातृभाषा का उपयोग करें। विदेशी वस्त्रों से परहेज नहीं किंतु पारिवारिक मंगल आयोजनों और उत्सवों में अपनी वेशभूषा धारण करें। स्वभूषा, उपासना पद्धति, भोजन हमारा होना चाहिए। इसी तरह हम पूरी दुनिया घूमकर आएं किंतु भारत के तपोस्थलों, तीर्थस्थलों, वीरभूमियों तक भी हमारा प्रवास हो। हमारे परिजन जानें की राणा प्रताप कौन हैं और चित्तौड़गढ़ कहां है। शिवाजी कौन थे और रायगढ़ कैसा है। जालियांवालाबाग कहां है। इसी तरह हमारे घर भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखने चाहिए। वहां एक भारतीय परिवार रहता है, यह प्रकट होना चाहिए। महापुरूषों की तस्वीरें।

जयंती

मंगल पांडे

जन्म: 19 जुलाई, 1827; मृत्यु: 8 अप्रैल, 1857) का नाम 'भारतीय स्वाधीनता संग्राम' में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है, जिनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बुरी तरह हिल गया था। मंगल पांडे की शहादत ने भारत में पहली क्रांति के बीज बोए थे। ब्रह्मदेश (बर्मा त्ववर्तमान म्यांमारत्व) पर विजय तथा सिक्ख युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर निष्कंटक राज्य करने के सपने देखें होंगे; पर उन्हें क्या पता था कि सन 1857 का वर्ष उनकी आशाओं पर तुषारपात का वर्ष सिद्ध होगा।

पुण्यतिथि

एनी मसकैरिनी

जन्म-6 जून, 1902; मृत्यु-19 जुलाई, 1963) संविधान सभा की सदस्य थीं। त्रावणकोर राज्य में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में वह शामिल थीं। साल 1951 में वह पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गयी थीं। भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इन्होंने संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनी मसकैरिनी इन्हीं में से एक थीं।

कल मिलेंगे

एक सज्जन बता रहे थे कि
वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं.
पता करने पर पता चला कि
गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

पुलिस-प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न करवाना

-दीपक कुमार त्यागी

पीआरवी एवं चीता मोबाइलों को कांवड़ मार्ग में और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर लगाया गया है। घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गयी हैं। दमकल की 12 गाड़ियां विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं, कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगें शिविरों की अनुमति देते समय ही आग से बचाव हेतु अग्निरोधी यंत्र, रेत की बाल्टी एवं पानी का ड्रम रखवाने के लिए शिविर आयोजकों को निर्देशित किया गया है। कांवड़ शिविरों में विद्युत सुरक्षा उपायों के किये जाने का निर्देश दिए गए हैं

हर वर्ष की तरह ही इस बार भी पवित्र श्रावण मास में देवाधिदेव भगवान महादेव के करोड़ों शिव भक्त को शांतिपूर्ण व भक्तिमय वातावरण में सकुशल कांवड़ यात्रा करवाना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। जिसको संपन्न करवाने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान का पुलिस-प्रशासन दिन-रात एक करके अपने पूरे दल-बल के साथ धरातल पर व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। पुलिस-प्रशासन को कांवड़ियों की संख्या में इस वर्ष भारी इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में विशेषकर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के पुलिस-प्रशासन के ऊपर पर एक तरफ तो जहां कांवड़ियों की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने कि अहम जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ इन करोड़ों शिवभक्त कांवड़ियों के लिए समुचित व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, जिसमें दोनों राज्यों का शासन व पुलिस-प्रशासन दिन-रात जुटा हुआ है।

वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से वर्ष दर वर्ष कांवड़ लाने वाले शिवभक्तों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निदेर्शों पर पुलिस-प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शिवभक्त कांवड़ियों का सेवाभाव के साथ पलक-पांवड़े बिछाकर के स्वागत किया जाता है और कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसका माइक्रो लेवल पर विशेष ध्यान रखा जाता है, इस स्थिति ने कांवड़ियों की संख्या में भारी इजाफा करने का कार्य कर दिया है। भारी-भीड़ की स्थिति में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए एक फुलप्रूफ, चाक-चौबंद व्यवस्था करना बेहद चुनौती पूर्ण कार्य बन गया है। कांवड़ यात्रा में विशेषकर के उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पुलिस-प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लाखों शिवभक्त कांवड़ियों के बीच छिपे हुए चंद अराजकता फैलाने की मंशा रखने वाले हुड़दंगियों की आखिरकार वह कैसे पहचान करें। हालांकि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पुलिस-प्रशासन के पास भक्तों की इस तरह की भारी भीड़ को नियंत्रण करने व उनके लिए समुचित व्यवस्था करने का दशकों पुराना लंबा अनुभव है, जिस अनुभव के ही बलबूते पर ही इन दोनों राज्यों का सिस्टम हर वर्ष ऐसे मेलों में उत्पन्न विकट से विकट परिस्थितियों से भी आसानी से निपट लेता है।

लेकिन इस बार शुरूआती दिनों से ही कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, शुरू के दिनों की बात करें तो प्रशासन के द्वारा 10 जुलाई से हरिद्वार में जल लेकर अपने गंतव्य स्थल पर जाने वाले कांवड़ियों की गिनती शुरू की गई थी। प्रशासन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई मंगलवार की शाम 6:00 बजे तक 80 लाख 90 हजार कांवड़िए गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य की तरफ वापस चल दिए, कांवड़ियों की यह संख्या प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं साथ ही चंद हुड़दंगियों के द्वारा बवाल भी किया जाने लगा है। जिसके चलते ही उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में शुरूआती दौर के दिनों में ही कांवड़ मार्ग के अधिकांश रास्तों को वन-वे तक करना पड़ गया है। हालांकि इससे आम लोगों को काफी असुविधा भी हो रही है। लेकिन पुलिस-प्रशासन क्या करें देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस स्थिति में कांवड़ियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए यह एक बेहद आवश्यक कदम है। इसलिए ही गंगा से लेकर मंदिर व कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब चप्पे-चप्पे पर होमगार्ड, ट्रेफिक पुलिस, पुलिस, पीएसी, आरएएफ, एटीएस आदि का सख्त पहरा नजर आने लगा है। घाटों पर एनडीआरएफ व गोताखोरों की टीम दल-बल के साथ तैनात हैं, कांवड़ यात्रा मार्ग पर जगह-जगह अग्निशमन विभाग के जांबाज भी तैनात हैं। वहीं पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी स्वयं पूरी टीम के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं और एक एक व्यवस्था को खुद परखने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इस बार शुरूआती दौर से ही कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हुए विवादों व तोड़फोड़ की कुछ घटनाओं ने पुलिस-प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि इस बार विवाद के अधिकांश मामलों को बिना वजह की ही बात के बतंगड़ बनाकर के तूल देने के प्रयास किए गए, जिन्हें पुलिस-प्रशासन ने तत्काल ही समझदारी से सूझबूझ दिखाते हुए शांत करवाने का कार्य करते हुए, हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए माहौल को सामान्य करने का कार्य बखूबी किया है। विवादों की इन चंद घटनाओं के चलते ही कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ पुलिस-प्रशासन का पूरा सिस्टम अचानक से हाई अलर्ट मोड पर चला गया है, सरकार व सिस्टम कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही व कोई भी चूक बिल्कुल भी नहीं चाहता है।

उदाहरणार्थ कांवड़ियों की सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सख्ती का आलम यह हो गया है कि गाजियाबाद तक में भी 14 जुलाई से ही रास्ते वन-वे या बंद कर दिए है। हालांकि रास्ते वन-वे होने से क्षेत्र के आम लोगों को जबरदस्त असुविधा हो रही है। लेकिन अलग कांवड़ यात्रा मार्ग ना होने से पुलिस-प्रशासन के पास अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखें तो इस बार उत्तराखंड में कांवड़ियों के जल भरने के सभी स्थान गोमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि से लेकर के उत्तर प्रदेश तक में भी पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों व चप्पे-चप्पे पर पुलिस व अर्द्ध सैनिक बलों के सुरक्षाकर्मियों का जाल बिछा दिया गया है, कंट्रोल रूम में बैठकर सुरक्षा विशेषज्ञ चप्पे-चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं।

कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था का आलम देखे तो गाजियाबाद जनपद में ही, पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी दीपक मीणा, नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल व अन्य सभी आवश्यक विभागों के मुखिया अपनी पूरी टीम के साथ चौबीसों घंटे मुस्तैद खड़े हुए नजर आते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ ने जनपद के करीब 80 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग को 124 बीटों में विभाजित कर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने चार स्थाई कंट्रोल रूम, एक मुख्य कंट्रोल रूम, दो सब कंट्रोल रूम और आठ स्टैटिक कंट्रोल रूम बनाए हैं। कांवड़ मार्ग को 1657 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है। 71 बैरियर लगाए गए हैं। 33 सार्वजनिक घोषणा प्रणाली बनाई गई है। 1560 पुलिस स्वयंसेवक व 10587 शांति समिति के सदस्य तैनात हैं।

पीआरवी एवं चीता मोबाइलों को कांवड़ मार्ग में और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर लगाया गया है। घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गयी हैं। दमकल की 12 गाड़ियां विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं, कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगें शिविरों की अनुमति देते समय ही आग से बचाव हेतु अग्निरोधी यंत्र, रेत की बाल्टी एवं पानी का ड्रम रखवाने के लिए शिविर आयोजकों को निर्देशित किया गया है। कांवड़ शिविरों में विद्युत सुरक्षा उपायों के किये जाने का निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मार्ग के निकट कोई नया बखेड़ा खड़ा ना हो इसके लिए मीट, मछली और अंडा आदि की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घट जाये इसलिए कांवड़ की ऊंचाई 10 फुट एवं चौड़ाई 12 फुट तक रखने के निर्देश दिए गए है। डाक कांवड़ में मानकों के अनुसार म्यूजिक सिस्टम पर 75 डेसीबेल तक का ही शोर मान्य है। यहां आपको बता दें कि इसी तरह की चाक-चौबंद व्यवस्था उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग के सभी जनपदों में की गई है।

इतनी चाक-चौबंद व्यवस्था के बाद भी पुलिस-प्रशासन के सामने कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाले दिनों किसी भी तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों से निपटने की बड़ी चुनौती खड़ी है। यात्रा के दौरान कांवड़ छूने, कांवड़ के वाहनों से टकराने, छुटपुट बातों का बतंगड़ ना बने उससे निपटने की चुनौती है। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों से देश में छोटे-बड़े की शर्म, भाईचारा और सामाजिक समरसता, आपसी सहयोग का भाव दिन-प्रतिदिन तेजी से कम होता जा रहा है, कांवड़ यात्रा में इसका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है, जिसके चलते ही अब बिना सिर-पैर के विवाद तक भी कांवड़ यात्रा में चंद हुड़दंगी पैदा करने लगे हैं। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस-प्रशासन जबरदस्त ढंग से सक्रिय है। सुरक्षा के मद्देनजर नियमित रूप से डॉग स्कवायड, बम निरोधक दस्ता और लोकल इंटेलीजेंस की टीम के साथ पुलिस चेकिंग अभियान चलाते हुए, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने में दिन-रात व्यस्त हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आराध्य देवाधिदेव भगवान महादेव के आशीर्वाद से कांवड़ यात्रा दिव्य अलौकिक बन कर सकुशल संपन्न होगी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

युवा भारत की कलम से लिखा निवेश का नया भूगोल

-संजीव कुमार मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार

उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचा और निवेश समर्थक नीतियों पर बल दिया है, उसका सीधा असर राज्य की आर्थिक चेतना पर पड़ा है। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राज्य के युवाओं की आकांक्षा का हिस्सा बन चुका है। आज का पूर्वांचल, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र भी बाजार की भाषा समझने लगा है

भारत की आर्थिक चेतना का जो नया अध्याय इस समय लिखा जा रहा है, उसकी सबसे सशक्त पंक्ति युवा भारत की कलम से निकल रही है। बीते वर्षों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, वे महज सरकारी योजनाओं या वैश्विक वित्तीय संस्थानों की रिपोर्टों के निष्कर्ष नहीं हैं, बल्कि भारत के गांवों, कस्बों और छोटे शहरों से निकलते उस नए युवा भारत के प्रमाण हैं जो अब सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि निवेश और उत्पादन का भागीदार बन चुका है। यह बदलाव जितना अदृश्य था, उतना ही व्यापक हो चुका है।

एक समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर विकास दर 3.5 से 4 प्रतिशत के बीच झूलती थी और इस स्थिरता को ही स्थायित्व मान लिया जाता था। 1950 से 1980 के दौर के लिए अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द प्रयोग किया। बाद के वर्षों में आशीष बोस ने बीमारू शब्द गढ़ा, जिससे बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की विकासहीनता को रेखांकित किया गया। लेकिन 2025 के इस कालखंड में यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जिन राज्यों को कल तक बीमारू कहा गया, आज वही आर्थिक परिवर्तन की नई इबारत लिख रहे हैं।

वर्ष 1991 में जब भारत ने उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया था, तभी से यह परिवर्तन धीरे-धीरे आकार लेने लगा था। किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि उस परिवर्तन का पूरा फल भारतीय जनमानस तक पहुंचने में समय लगा। किंतु अब स्थिति बदल चुकी है। भारत के शेयर बाजार को लेकर जितना उत्साह आज छोटे शहरों और ग्रामीण अंचलों में देखने को मिल रहा है, वह इस बात का प्रमाण है कि देश की आर्थिक यात्रा अब कुछ महानगरों तक सीमित नहीं है। और इस समावेशी आर्थिक चेतना का नेतृत्व कर रहे हैं देश के युवा।

मॉर्गन स्टैनली जैसी वैश्विक वित्तीय संस्था का यह आकलन कि यदि स्थितियां अनुकूल रहीं, तो भारत का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स अगले 12 महीनों में एक लाख के आंकड़े को पार कर सकता है, केवल बाजार का भविष्यवाणीय अनुमान नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में आ रहे गहरे और बुनियादी बदलावों का संकेत भी है। इस आकलन के पीछे जिस प्रवृत्ति ने सबसे अधिक प्रभाव डाला है, वह है-निवेश के प्रति युवाओं की रुचि, जागरूकता और भागीदारी।

यदि हालिया वर्षों में निवेशक संख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बदलाव केवल महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक जैसे पारंपरिक औद्योगिक राज्यों तक सीमित नहीं है। बल्कि अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्य इस दौड़ में शामिल ही नहीं, बल्कि कई मायनों में अग्रणी भी हो चले हैं।

वित्तीय वर्ष 2025 के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि भारत में सबसे अधिक डीमैट खाताधारक महाराष्ट्र में हैं, जिसकी संख्या लगभग 186 लाख है। किंतु इसके बाद दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहां यह संख्या 130 लाख के आसपास पहुंच गई है। विशेष बात यह है कि जबकि महाराष्ट्र ने पांच वर्षों में लगभग 21 गुना वृद्धि दर्ज की, उत्तर प्रदेश ने 47 गुना की दर से यह वृद्धि हासिल की है। इससे यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं कि महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां निवेश स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अब निवेशक वर्ग के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचा और निवेश समर्थक नीतियों पर बल दिया है, उसका सीधा असर राज्य की आर्थिक चेतना पर पड़ा है। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राज्य के युवाओं की आकांक्षा का हिस्सा बन चुका है। आज का पूर्वांचल, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र भी बाजार की भाषा समझने लगा है।

इसी क्रम में राजस्थान की स्थिति भी उल्लेखनीय है, जहां पांच वर्षों में 46 गुना तक निवेशकों की संख्या में वृद्धि हुई है। पर्यटन और खनिज संपदा पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस राज्य में अब युवाओं ने बाजार को भी संभावनाओं का क्षेत्र मानना शुरू कर दिया है। किंतु जो राज्य सबसे अधिक चौंकाता है, वह है-बिहार।

एक समय लालटेन की राजनीति से पहचान रखने वाला बिहार अब 'लैपटॉप और लिक्विडिटी' की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। पांच वर्षों पहले जहां बिहार में केवल सात लाख लोग शेयर बाजार से जुड़े थे, वहीं अब यह संख्या 52 लाख को पार कर चुकी है। यह 68 गुना वृद्धि न केवल देश की सबसे तेज आर्थिक भागीदारी को दशार्ती है, बल्कि उस मानसिक और सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है जो इस राज्य की जनता में आया है।

बिहार में हाल के वर्षों में आयोजित औद्योगिक संवाद और निवेशक समागमों में देश की 55 से अधिक आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने भाग लिया है। ये कंपनियाँ ड्रोन, डेटा सेंटर, सोलर उपकरण और सॉफ्टवेयर सेवाओं में रुचि दिखा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए 70 प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि, सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था और उद्योगिक संवाद में तत्परता इस बदलाव को और मजबूती दे रहे हैं। यह बदलाव केवल योजनाओं या घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर दिखने लगा है।

आज बिहार का युवा केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में ही नहीं लगा, बल्कि वह SIP, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के उतार-चढ़ाव को भी समझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों तक Zerodha, Groww AaSX Upstox जैसे प्लेटफॉर्म्स की पहुंच, और साथ में स्मार्टफोन व इंटरनेट की उपलब्धता ने वित्तीय जागरूकता की सीमा को तोड़ दिया है। अब समस्तीपुर का एक छात्र SIP की शुरूआत करता है, दरभंगा की गृहिणी म्यूचुअल फंड में निवेश करती है, और पूर्णिया का एक किसान अपने बेटे के लिए टैक्स प्लानिंग सीख रहा है।

यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे शिक्षा तक पहुंच, इंटरनेट और मोबाइल क्रांति, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी का लोकतंत्रीकरण, और आर्थिक आत्मनिर्भरता की बढ़ती चाहत का योगदान है। अब सरकारी नौकरी को ही जीवन की उपलब्धि मानने वाली सोच में परिवर्तन आया है। युवाओं में अब जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, और निवेश को सिर्फ अमीरों का खेल मानने का भ्रम टूट चुका है।

इस समूचे परिदृश्य में यह स्वीकार करना आवश्यक है कि भारत की आर्थिक उन्नति केवल जीडीपी, सेंसेक्स या विदेशी निवेश से नहीं मापी जा सकती। वास्तविक बदलाव तब स्थायी होगा जब देश के हर हिस्से को इसमें समान भागीदारी का अवसर मिलेगा।

भारत यदि विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है, तो उसे अपने आर्थिक मॉडल को महानगरों से निकालकर दरभंगा, आरा, प्रयागराज और अजमेर जैसे शहरों की गलियों तक ले जाना होगा। यह नई आर्थिक कहानी केवल आंकड़ों की नहीं, आत्मविश्वास की भी कहानी है।

सेंसेक्स कब एक लाख के आंकड़े को पार करेगा, इस पर विचार हो सकते हैं, बहस हो सकती है। लेकिन यदि बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गांवों में आर्थिक आत्मनिर्भरता की लौ जल उठी है, तो यही असली आर्थिक क्रांति है। और यदि यह यात्रा युवा नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, तो यह भी स्पष्ट है कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

बांग्लादेश में जुलाई क्रांति के 1 साल, कट्टरपंथियों ने ढाका बंद का किया ऐलान

(एजेन्सी)।

बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के गढ़ गोपालगंज में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह झड़प नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) की रैली के दौरान हुई, जो फरवरी में छात्रों के द्वारा बनाई गई एक नई पार्टी है। इस संघर्ष में अब कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने 19 जुलाई को बांग्लादेश बंद का ऐलान किया है। जमात-ए-इस्लामी 20 वर्षों के बाद 19 जुलाई को ढाका के ऐतिहासिक सहरावर्दी उद्यान में बड़ी रैली करने जा रही है। रैली में जमात के अलावा इस्लामिक मूवमेंट, खिलाफते मजलिस जैसे कट्टरपंथी संगठन शामिल हो सकते हैं।

बंगबंधु समाधि परिसर पर गैरकानूनी और भड़काऊ भीड़ के हमले को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम एक दर्जन नागरिकों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की आशंका है। इस साल की शुरूआत में पद से हटाए जाने के बाद अपने पहले बड़े राजनीतिक हस्तक्षेप में, शेख हसीना ने यूनुस पर निशाना साधते हुए उन्हें हत्यारा-फासीवादी, राष्ट्र-विरोधी षड्यंत्रकारी और भीड़ आतंकवाद का गॉडफादर कहा। उन्होंने कहा कि देश ने देखा कि किसने हमारे झंडे, हमारे संविधान और राष्ट्रपिता की समाधि का अपमान किया। बंगबंधु और बांग्लादेश एक हैं। बंगबंधु पर कोई भी हमला इस देश की आत्मा पर हमला है और बंगाली लोग इसे माफ नहीं करेंगे।

उन्होंने दावा किया कि यह हिंसा 5 अगस्त की घटना का ही एक रूप है। अवामी लीग के कार्यालयों और स्मारकों पर पहले हुए हमलों का ज़िक्र करते हुए और यूनुस पर उग्रवादी तत्वों को भड़काने और राज्य को अस्थिर करने का आरोप लगाया।

'मैं उन कहानियों में विश्वास करती हूँ जो लोगों को छू जाएँ': सानिया नूरैन

(एजेन्सी)।

अपनी शांत भाव-भंगिमा और लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ, अभिनेत्री सानिया नूरैन आज भारतीय मनोरंजन जगत में उभरते हुए चेहरों में से एक बनती जा रही हैं। टीवी शो 'निमकी मुखिया' में महुआ के किरदार से अपने करियर की शुरूआत करने वाली सानिया अब हाल ही में रिलीज हुए आत्मीय संगीत वीडियो कर फैसला में एक नए रंग में नजर आईं हैं। उनकी यह यात्रा न केवल सधी हुई अभिनय प्रतिभा को दशार्ती है, बल्कि उनके चयनित किरदारों में गहराई और भावनात्मक पकड़ भी देखने को मिलती है। कर फैसला में सानिया के साथ नजर आए जाने-माने पार्श्वगायक आमन त्रिखा, जिनके गाए गाने 'हुक्का बार' और 'प्रेम लीला' जैसी हिट्स रह चुके हैं। जहाँ त्रिखा की आवाज इस गाने की आत्मा को स्वर देती है, वहीं सानिया की अदायगी इसे एक अलग ही गहराई प्रदान करती है। उन्होंने केवल अभिनय नहीं किया-उन्होंने हर भावना को आत्मसात किया और उसे ईमानदारी से परदे पर उतारा। सानिया कहती हैं, "मैं उन कहानियों में विश्वास करती हूँ जो लोगों को भीतर तक छू जाती हैं। कर फैसला ने मुझे यह मौका दिया-बिना संवादों के दर्द, शक्ति और मौन को अभिव्यक्त करने का। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। इस म्यूजिक वीडियो की सिनेमैटोग्राफी, मार्मिक बोल और संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली कहानी सानिया के भावपूर्ण अभिनय को और अधिक निखार देती है। दर्शकों ने उनके अभिनय में झलकती संवेदनशीलता और शांत ताकत की सराहना की है, साथ ही उनके दृश्यात्मक प्रभाव को भी काफी सराहा है। यह पहली बार नहीं है जब सानिया ने दर्शकों का दिल जीता हो। निमकी मुखिया और इसके सीक्वल निमकी विधायक में उन्होंने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई थी। यह शो सामाजिक मुद्दों पर आधारित था और 600 से अधिक एपिसोड तक चला-जो अपने आप में एक उपलब्धि है। महुआ का किरदार, जिसकी ईमानदारी और भावनात्मक गहराई दर्शकों के दिलों में उतर गई, सानिया के अभिनय की असली पहचान बना।

अब सानिया जल्द ही नजर आएँगी आगामी वेब सीरीज सरकारी दमाद में, जिसमें नजर आएँगे व्यंग्य, ड्रामा और मनोज तिवारी के गानों से सजा एक शानदार साउंडट्रैक। हालाँकि फिलहाल शो के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, पर दर्शकों की उम्मीदें जरूर ऊँची हैं। सानिया नूरैन की यात्रा को खास बनाता है उनका विश्वास-सिर्फ भूमिकाओं का चयन नहीं, बल्कि उनका मकसद और जुड़ाव।

अदिति चौहान ने किया रिटायरमेंट का ऐलान

(एजेन्सी)।

भारत की स्टार फुटबॉलर अदिति चौहान ने शुक्रवार, 18 जुलाई को अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वहीं संन्यास के बाद अदिति ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार गेंद को किक मारी थी, तब उन्हें नहीं पता था कि भारत की नेशनल विमेंस फुटबॉल टीम भी है। अदिति ने शुक्रवार को संन्यास लेने की घोषणा की थी। वह अपने बेहतरीन करियर के दौरान यूरोप में पेशेवर फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। इस 32 वर्षीय खिलाड़ी ने पीटीआई वीडियो से कहा कि, पहली बार फुटबॉल खेलते समय मुझे ये नहीं पता था कि कोई राष्ट्रीय टीम भी है। मैंने शौकिया तौर पर फुटबॉल खेलना शुरू किया था। जब मैंने शुरूआत की थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचने में सफल रहूंगी। मैंने अपने करियर में जो कुछ भी हासिल किया, वह कोई सपना भी नहीं था जिसकी मैं कल्पना कर सकती थी। अदिति चौहान पूर्णकालिक कोचिंग में प्रवेश नहीं कर रही हैं, लेकिन अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को शीर्ष स्तक की फुटबॉल में अपने लक्ष्य हासिल कनरे में मदद करने के लिए तैयार हैं। भारतीय महिला टीम की पूर्व गोलकीपर अदिति ने अपने 17 साल के दौरान राष्ट्रीय टीम के साथ-साथ अपने क्लबों के लिए भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं।

अपडेट नहीं कराया तो बंद हो जाएगा बच्चे का आधार कार्ड

(एजेन्सी)।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइ) ने अभिभावकों से बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने का आग्रह किया है। यह अनुरोध उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिनकी आयु सात वर्ष हो गई है और जिनके आधार में बायोमेट्रिक्स अपडेट होने हैं। गौरतलब है कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को केवल उनकी तस्वीर और जनसांख्यिकीय विवरण के आधार पर आधार जारी किया जाता है, और उनकी बायोमेट्रिक जानकारी, जैसे कि उंगलियों के निशान या आईरिस बायोमेट्रिक्स, दर्ज नहीं की जाती। जब बच्चा सात वर्ष का हो जाता है, तो उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और एक अपडेट की गई तस्वीर जैसी बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक हो जाती है, इस प्रक्रिया को पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कहा जाता है।

यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि बायोमेट्रिक डेटा की विश्वसनीयता और सटीकता बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक अपडेट का समय पर पूरा होना बेहद जरूरी है। यूआईडीएआई के बयान में कहा गया है कि अगर 7 साल की उम्र के बाद भी एमबीयू पूरा नहीं किया जाता है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार, आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है। यूआईडीएआई ने अपने बयान में आगे कहा कि माता-पिता/अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों/वार्ड के बायोमेट्रिक्स को प्राथमिकता के आधार पर आधार में अपडेट करें। एजेंसी ने उपयोगकर्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजकर सूचित करना शुरू कर दिया है, जिसमें उनसे पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) पूरा करने का आग्रह किया जा रहा है।

बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने के लिए, माता-पिता किसी भी आधार सेवा केंद्र या किसी निर्दिष्ट आधार केंद्र पर जा सकते हैं। यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि पाँच से सात साल की उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क है। 100 रुपये का अपडेट शुल्क केवल तभी लिया जाएगा जब बच्चा 7 साल की उम्र पार कर ले। इस बीच, जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यूआईडीएआई ने मृतक व्यक्तियों के पहचान प्रमाण के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनके आधार को निष्क्रिय करना शुरू कर दिया है और अब तक 1.17 करोड़ से अधिक ऐसे 12 अंकों वाले विशिष्ट नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है।

पत्रकार एसोसिएशन प्रयागराज की बैठक मीडिया सेंटर कार्यालय लालापुर में संपन्न

संजना भारती संवाददाता

बारा प्रयागराज। पत्रकार एसोसिएशन प्रयागराज की बैठक शुक्रवार को मीडिया सेंटर कार्यालय लालापुर में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम लाला शुक्ला (तहसील सचिव) ने पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पी.सी.पाण्डेय का माल्यार्पण कर स्वागत किया। ततपश्चात बैजनाथ शुक्ला को मंडल सलाहकार के रूप में सदस्यता दिलाई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पी.सी. पाण्डेय ने कहा कि "सत्यता, सटीकता, निष्पक्षता, स्पष्टता, और समयबद्धता। एक पत्रकार को तथ्यों की जाँच करके सटीक जानकारी देनी चाहिए, किसी भी पक्ष का समर्थन किए बिना निष्पक्ष रहना चाहिए, और जानकारी को स्पष्ट और समझने में आसान तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। पत्रकार को अपनी व्यक्तिगत राय या पक्षपात से बचना चाहिए, और तथ्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रस्तुत करना चाहिए।

पत्रकार को घटनाओं की तह तक जाना चाहिए और व्यापक संदर्भ प्रदान करना चाहिए, ताकि पाठक समझ सकें कि क्या हो रहा है और क्यों....? इस दौरान दीपचंद्र शुक्ला, मनोज त्रिपाठी, दीपक पाण्डेय, संजयधर द्विवेदी, बैजनाथ शुक्ला, प्रशांत पाठक, अवधेश पांडेय सहित कई लोग रहे...।

संगठन मजबूती पर परिचर्चा का आयोजन

एसबी ब्यूरो

बेगूसराय। जदयू प्रदेश प्रवक्ता सह न्यास बोर्ड के सदस्य हेमराज राम, जिलाध्यक्ष रुदल राय, प्रदेश राजनैतिक सलाहकार समिति सदस्य अशोक पटेल और ऑर्थोपेडिक सर्जन सह प्रदेश राजनैतिक सलाहकार समिति सदस्य डॉ. प्रवीण कुमार साथ में संगठन मजबूती और बीएलए 2 की नियुक्ति और फॉर्म पर चर्चा का आयोजन किया गया।

प्राथमिक चिकित्सा एवं दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इंतजार हुसैन

बदायूं। कल्याण चौक, बाइपास उझानी पर औषधि निरीक्षक बदायूं लवकुश प्रसाद एवं बदायूं एसोसिएशन से शिव स्वरूप गुप्ता की उपस्थिति में सावन के महीने में कांवड़ियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा एवं दवा वितरण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस कैम्प के माध्यम से औषधि निरीक्षक बदायूं लवकुश प्रसाद ने मार्ग से गुजर रहे कांवड़ियों को जरूरत के अनुसार दवाइयाँ, ओआरएस, पेन-किलर टेबलेट्स, दर्द के ट्यूब, विटाडीन ट्यूब, पट्टी, बैंडेड आदि वितरित किये।

इस अवसर पर उझानी केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश गोयल, मंत्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल एवं राजीव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष डॉ मोहित अग्रवाल, कैम्प संचालक राजकुमार माहेश्वरी, प्रदीप साहू, डॉ हबीब कादरी, डॉ गीतम सिंह, मोहसिन रजा, इमरान जोंटी, वेदप्रकाश, अमित साहू, कमलजीत सक्सेना, निशान्त वार्ष्णेय, रोबिन जैन, केजीएन, संतोष वार्ष्णेय आदि उपस्थित रहे।

हमारा उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना-सीपी सिंह

एसबी ब्यूरो

तेघड़ा(बेगूसराय)। अवकाश प्राप्त वायुसेना के वरीय पदाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी ने लगातार 143 विधानसभा क्षेत्र में जनसमपर्क अभियान चला रहे है।डोर-टू-डोर मतदाताओं से मिलकर अपनी संकल्प से लोगों को अवगत करा रहें हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान चंद्रप्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, पलायन, गरीबी और बेरोजगाड़ी को रोकना, अपने क्षेत्र में 50.000 जॉब उपलब्ध कराना, आदर्श

ग्राम की रुपरेखा तैयार कर उसे आदर्श ग्राम में परिणत करना, लगभग हर गांव में शिक्षा का हब बनाना और बच्चों को आईएएस, पीसीएस और बैंकिंग सेवाओं के लिए तैयार करना, कैंट परीक्षा के लिए मुफ्त में कोचिंग देना और लगभग हर साल 1 हजार राष्ट्रीय स्तर पर मैनेजर आईआईएम तैयार करना, हर छोटी-बड़ी समस्याओं का निदान शीघ्र करना,100 प्रतिशत साक्षरता के लिए तैयारी करना, सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, मॉडल स्कूल की रुप रेखा तैयार कर उसे अंजाम देना, सहित अन्य उद्देशों को जन-जन को सुनाया।

बाल संसद का गठन, पिंकी शर्मा ने किया अपने मंत्रीमंडल के सदस्यों के साथ शपथग्रहण

संजना भारती संवाददाता/एस रहमान

टोंक। पीपलू ममता हेल्थ इंस्टिट्यूट फार मदर एण्ड चाईल्ड एवं डेटॉल बनेगा स्वास्थ्य इंडिया के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयकिशनपुरा में बाल संसद का गठन किया गया। इस आयोजन में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री पिंकी शर्मा, उप प्रधानमंत्री रिद्धिमा गुर्जर, स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्री तमन्ना गुर्जर, जल व पर्यावरण मंत्री लोकेश शर्मा, सांस्कृतिक मंत्री गुड्डी गुर्जर, शिक्षा मंत्री अक्षिता शर्मा, खेल मंत्री अजय गुर्जर, सुरक्षा वन न्याय मंत्री अजय गुर्जर, बागवान मंत्री दिलकुश बलाई, पुस्तकालय मंत्री प्रीति गुर्जर, सूचना व जनसंपर्क मंत्री रामकेश गुर्जर को मनोनीत किया गया और इन पदों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रधानाध्यापक हेमराज माली, दिनकर विजय वर्गीय, मोरपाल गुर्जर, घनश्याम लक्षकार, मोहन गुर्जर, शंकर लाल मीणा, कन्हैया लाल शर्मा, अंकित कुमार, निरमा चौधरी मौजूद रहे। छात्रों ने यह पद पाकर बहुत खुशी जताई।

बागबानी विभाग द्वारा करवाये गये राज्य स्तरीय नाशपाती मुकाबले में अमृतसर के किसानों ने मारी बाजी

पंजाब सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कर रही है ठोस प्रयास-मोहिंद्र भगत

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़/अमृतसर। बागबानी विभाग द्वारा जिला अमृतसर में महाराजा फार्म में दो दिवसीय राज्य स्तरीय नाशपाती का शो और सैमीनार लगाया गया, जिसमें रक्षा सेवा कल्याण, स्वतंत्रता संग्रामी और बागबानी मंत्री श्री मोहिंद्र भगत मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए और इस शो का उद्घाटन किया।

इस मौके पर बागबानी मंत्री श्री मोहिंद्र भगत ने किसानों को संबोधन करते हुये कहा कि पंजाब सरकार राज्य के बागबानी क्षेत्र का विकास करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आज का यह नाशपती मुकाबला भी इन प्रयासों का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुकाबले, प्रदर्शनियां, सैमीनार जहाँ किसानों की जानकारी बढ़ाते हैं, वहीं उनके व्यापारिक सम्बन्ध भी बनते हैं जोकि किसानों की आय बढ़ाने में अच्छा योगदान डालते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार इस बार किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुँचाने में कामयाब रही है और इससे राज्य के बागबानी क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिला है। इस मौके पर बागबानों द्वारा उनको पेश आ रही

मुश्किलों को बागबानी मंत्री और डायरैक्टर बागबानी के संज्ञान में लाया गया जिसका उनकी तरफ से जल्द निपटारा करने का भरोसा दिया गया।

इसके इलावा डिप्टी डायरैक्टर बागबानी, अमृतसर श्री तजिन्दर सिंह संधू द्वारा समागम सम्बन्धी बताया गया कि राज्य के विभिन्न जिलों से बागबानों द्वारा बढ़िया मानक और उच्च गुणवत्ता के नाशपाती फल और फलों से तैयार फल पदार्थों की 714 रखी ऐंट्रियों का मुकाबला करवाया गया और विजेताओं को पहले और दूसरे दर्जे के इनाम मुख्य मेहमान द्वारा दिए गए। इस मुकाबले में जिला अमृतसर 28 इनाम प्राप्त करके पहले नंबर पर रहा। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियाँ भी लगाईं गई और बागबानों को नाशपाती की काश्त और मंडीकरण के बारे पी.ए.यू. लुधियाना से आए माहिरों द्वारा जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर समागम में एस.डी.एम. स. गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, सहायक डायरैक्टर बागबानी श्री जतिन्दर सिंह संधू, सुखपाल सिंह, हरविन्दर सिंह, तेजबीर सिंह, किरनबीर कौर, हरप्रीत कौर (सभी बागबानी विकास अधिकारी) और मनीस्टीरियल और फील्ड स्टाफ ने समागम को कामयाब करने में अहम योगदान डाला।

मुख्यमंत्री ने दोहराया-नशा तस्करी के बड़े 'जरनेलों' पर कोई रहम नहीं

कहा-खुद को अजेय समझने वालों को सलाखों के पीछे डाला?

संजना भारती संवाददाता

मालेरकोटला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि राज्य में नशे के जहर को फैलाने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और खुद को अजेय समझने वाले नशा तस्करी के 'जनरल' अब सलाखों के पीछे हैं।

अहमदगढ़ और अमरगढ़ में नए तहसील कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे का धंधा उन लोगों की सरपरस्ती में फलता-फूलता रहा, जिन्हें जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना था, लेकिन दुर्भाग्यवश वे ही लोग सरकारी गाड़ियों से नशा सप्लाई करते रहे। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के पास अपने शासनकाल में असीम ताकत थी, लेकिन नशा तस्करों से मिलीभगत के चलते कोई उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने ऐसे नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा क्योंकि उन्होंने नशे के कारोबार के माध्यम से पंजाब की युवा पीढ़ी को बर्बाद किया।

मुख्यमंत्री ने पंजाब के इन "गद्दारों" को सबक सिखाने के लिए जनता से पूर्ण समर्थन और सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि " युद्ध नशों विरुद्ध" की शानदार सफलता इस बात का प्रमाण है कि पंजाब की जनता इस लड़ाई में सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुहिम आगे भी निरंतर जारी रहेगी ताकि पंजाब को नशे की इस लानत से पूरी तरह मुक्त किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बादल-मजीठिया परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि सत्ता की लड़ाई के चलते अंदरूनी झगड़े चरम पर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल आपसी फूट का शिकार हैं क्योंकि इनके नेता केवल सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। भगवंत मान ने कहा कि सत्ता के भूखे ये नेता अब बेचैन हैं क्योंकि जनता ने 'आप' को चुना और इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार आने वाले समय में कई जनकल्याणकारी निर्णय लेगी जिससे सभी को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनें। उन्होंने जोर दिया कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से एक समृद्ध और खुशहाल पंजाब का निर्माण किया जाएगा।

बेअदबी की घटनाओं को रोकने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार को विधानसभा में पंजाब धार्मिक ग्रंथों संबंधी अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है जो सभी पंजाबियों को प्रभावित करता है और वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे घृणित अपराधों में लिप्त लोगों के लिए सख्त सजा अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब संतों, गुरुओं और पैगंबरों की पवित्र भूमि है जिन्होंने प्रेम, सद्भाव और सहिष्णुता का संदेश दिया। उन्होंने अफसोस जताया कि कुछ पंजाब विरोधी ताकतें 2016 से धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं को अंजाम देकर सामाजिक एकता को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। भगवंत मान ने ऐसे अपराधियों को उदाहरणात्मक सजा देने के प्रति अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।

जनहित में अपनी सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की जानकारी दी और बताया कि यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है जो हर पंजाबी परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराती है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सभी घरों को इस तरह की व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक नेताओं ने अपने संदेहास्पद आचरण से जनता का विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब विरोधी और जनविरोधी रुख के कारण जनता ने कांग्रेस और अकाली दल को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि वह सौभाग्यशाली हैं कि राज्य की जनता ने भारी बहुमत से उनकी सरकार को सत्ता में लाकर अपार स्नेह और समर्थन दिया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि उनकी सरकार ने अपने साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में 55,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं और पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं में विश्वास बढ़ा है और अब वे विदेश जाने की बजाय राज्य में ही सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने खराब मौसम के बावजूद सभा में उपस्थित लोगों का आभार जताया और कहा कि यह परियोजनाएँ नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान कर उन्हें बहुत लाभ देंगी। उन्होंने बताया कि राज्य भर में इसी प्रकार के आधुनिक तहसील कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके ही शहरों में सभी नागरिक सेवाएं आसानी से मिल सकें। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी आम जनता की सुविधा के लिए इस तरह के प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का शासन पहले गलत हाथों में था, जिसकी वजह से पंजाब को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब सरकार ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दे रही है जो जनहित से सीधे जुड़े हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भवनों का निर्माण जनता की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने "आसान रजिस्ट्री" और "आसान जमाबंदी" जैसे अभिनव सुधार लागू किए हैं ताकि लोग अपने घरों में ही जरूरी सेवाएं प्राप्त कर सकें। इन पहलों से लोगों को असुविधा से राहत मिलेगी और समयबद्ध सेवाओं की गारंटी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह समर्पित है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही: पटियाला डिवीजन जीएसटी वृद्धि में अग्रणी, लुधियाना डिवीजन राजस्व प्राप्ति में शीर्ष पर

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान, पटियाला जीएसटी डिवीजन ने जीएसटी राजस्व प्राप्ति में 40 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज करते हुए पंजाब के अन्य सभी डिवीजनों से अग्रणी रही है। यह खुलासा वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में हुई आबकारी एवं कराधान विभाग की तिमाही समीक्षा बैठक के दौरान किया गया। पटियाला डिवीजन के बाद, रोपड़ डिवीजन की विकास दर 34.97 प्रतिशत और अमृतसर डिवीजन की 30.26 प्रतिशत रही। विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी ढंग से नकेल कसते हुए अपने आबकारी राजस्व लक्ष्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। जहाँ पटियाला डिवीजन ने विकास दर में अग्रणी भूमिका निभाई, वहीं लुधियाना डिवीजन ने राज्य भर में सबसे अधिक कुल जीएसटी राजस्व दर्ज किया, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में 23.89 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करते हुए 1998.76 करोड़ रुपये रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में रोपड़ डिवीजन ने 1315.66 करोड़ रुपये, अमृतसर डिवीजन ने 687.19 करोड़ रुपये और पटियाला डिवीजन ने 679 करोड़ रुपये जीएसटी राजस्व के रूप में प्राप्त किए। ये आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से काफी वृद्धि दर्शाते हैं, जहाँ लुधियाना डिवीजन ने 1613 करोड़ रुपये, रोपड़ डिवीजन ने 975.53 करोड़ रुपये, अमृतसर डिवीजन ने 527.54 करोड़ रुपये और पटियाला डिवीजन ने 484.98 करोड़ रुपये जीएसटी राजस्व के रूप में प्राप्त किए थे।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डिवीजनों में तैनात विभाग की टीमों के समर्पण और

अथक प्रयासों की सराहना की और अन्य डिवीजनों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इन डिवीजनों के प्रभारियों, डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स, के साथ विस्तृत चर्चा की और उन क्षेत्रों का पता लगाया जहाँ उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, साथ ही उन पहलुओं की पहचान की जिनमें और सुधार की आवश्यकता है।

बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने जीएसटी और वैट बकाया की स्थिति की भी समीक्षा की और विभाग के अधिकारियों को इसकी वसूली के लिए नवीन रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने चल रही जीएसटी जांच की प्रगति का भी मूल्यांकन किया, जिसमें पहली तिमाही के दौरान की गई जांचों की गिनती और निपटाए गए केस शामिल थे। उन्होंने विभाग को सभी लंबित मामलों के समय पर निपटाने के निर्देश जारी किए। इस अवसर पर, आबकारी और कराधान दोनों विभागों के प्रवर्तन विंगों के प्रदर्शन की भी विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान कर चोरी को रोकने के लिए स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रीवेंटिव यूनिट के प्रयासों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, आबकारी टीमों द्वारा अवैध शराब और अन्य राज्यों से पंजाब में शराब की तस्करी से निपटने के लिए अपनी प्रवर्तन गतिविधियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वित्त मंत्री ने प्रवर्तन विंगों के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया और उन्हें अपने प्रयासों को और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

अंत में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी और वैट अपील केसों की स्थिति की समीक्षा की और मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लंबित और नए शुरू किए गए मामलों का पता लगाया। उन्होंने इन सभी मामलों पर निरंतर और गंभीरता से फलो-अप कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया।

हरविन्द्र कल्याण ने घरौंडा हलके को दी सवा करोड़ की दो विकास परियोजनाओं की सौगात

■ भोला कालोनी में 31 लाख 20 हजार की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र और 69 लाख में नगरपालिका घरौंडा के अधीन बनने वाले रास्ते का किया शिलान्यास

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने शुक्रवार को घरौंडा हलके में सवा करोड़ की दो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। घरौंडा के वार्ड-6 में भोला कॉलोनी में 31 लाख 20 हजार की लागत से बनने वाला सामुदायिक केंद्र और 69 लाख 8 हजार की लागत से नगरपालिका क्षेत्र के अधीन घरौंडा से बसताड़ा रोड से तेलू राम डेरा तक बनाए जाने वाला तीन हजार फुटे लंबे राजस्व रास्ते के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने सफाई सर्वेक्षण में देश में करनाल को तीसरा, सोनीपत को 38 वां और घरौंडा को जिला में पहला स्थान मिलने पर सभी आमजन को बधाई दी। साथ ही भविष्य में भी घर और आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाए रखने और सफाई को आदत में शुमार करने की अपील की।

विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने नगरपालिका घरौंडा के अधीन पड़ने वाले क्षेत्र घरौंडा से बसताड़ा रोड से तेलू राम डेरा तक राजस्व रास्ते के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पेवर ब्लाक से बनाए जाने वाले तीन हजार फुट लंबे इस रास्ते के निर्माण पर 69. 08 लाख रुपये खर्च होंगे। रास्ते की चौड़ाई 16.5 फुट है। इसे नगरपालिका घरौंडा द्वारा बनवाया जा रहा है। निर्माण कार्य छह महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद उन्होंने घरौंडा के वार्ड-6 की भोला कॉलोनी में सामुदायिक केंद्र के हॉल का शिलान्यास किया। इस पर 31.20 लाख रुपये की लागत आएगी। हॉल 44 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा बनेगा।

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि हॉल की मांग काफी पुरानी थी जो अब पूरी होने जा रही है। स्थान निश्चित न होने के कारण इसमें कुछ देरी जरूर हुई। उन्होंने अधिकारियों को हॉल को हवादार, पर्याप्त ऊंचाई वाला व अन्य मूल सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए कहा है। भविष्य में जरूरत अनुसार नई मंजिलें बनाकर इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने सफाई सर्वेक्षण में करनाल को देश में तीसरा और घरौंडा को जिला में प्रथम स्थान पाने पर नगर पालिका की पूरी टीम, चेयरमैन, पार्षदों अधिकारियों, कर्मचारी, लोगों और सफाई कर्मचारियों को बधाई। लोगों से अपील की कि घर की सफाई के साथ-साथ गली-मोहल्ले की सफाई की भी चिंता करें और कूड़ा-कर्कट इधर-उधर न फैंकें। सफाई रखने से कई बीमारी से भी बचा जा सकता है।

26 व 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा के लिए सरकार की पूरी तैयारी-मुख्यमंत्री

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं की मांग को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश में दूसरी सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने सीईटी की परीक्षा को लेकर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। प्रदेशभर से सीईटी ग्रुप-सी के लिए 13 लाख 87 हजार युवाओं ने आवेदन किया। इन आवेदकों की 26 व 27 जुलाई को परीक्षा ली जा रही है। युवाओं को परीक्षा केंद्र तक लेकर जाने और वापस छोड़ने के लिए 9200 बसों की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहा कि बस सुविधा के लिए युवाओं से रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों के अलावा प्राइवेट स्कूलों की बसों को भी सीईटी परीक्षा के लिए तैयार किया है। इसके लिए प्राइवेट स्कूलों से आग्रह किया था, ताकि युवाओं और बेटियों को सुविधा मुहैया करवाई जा सके। परीक्षा के समय युवतियों के साथ परिवार का एक सदस्य भी पेपर के समय फ्री में यात्रा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने रॉबर्ट वाड्रा के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लंबे समय से उन पर केस चल रहा था जिसकी जांच चल रही थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक कई गलतियां और भ्रष्टाचार को किया हुआ है जो किसी न किसी दिन तो सामने आने ही थे।

राजौंद-कैथल खस्ताहाल सड़क पर वाहन हो रहे दुर्घटनाग्रस्त

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। राजौंद की खस्ताहाल सड़क पर वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। यात्री चोटील हो रहे हैं। सरकार व प्रशासन से राजौंद मार्केट कमेटी ने प्रार्थना की है कि इस मार्ग को वाहनों के चलने लायक बनाया जाए।

खाद विक्रेता किसानों को उचित मात्रा में खाद उपलब्ध करवाना करें सुनिश्चित: डॉ वजीर सिंह

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने शुक्रवार को खाद के थोक व खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में डॉ वजीर सिंह ने खाद विक्रेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

डॉ वजीर सिंह ने खाद विक्रेताओं को निर्देश दिये कि किसानों को उनकी मांग अनुसार उचित मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए। साथ ही खाद किसी भी पड़ोसी राज्य अथवा जिला में न भेजी जाए। खाद के उपलब्ध स्टॉक व पोस मशीन के स्टॉक का सही मिलान किया जाये। प्रत्येक विक्रेता के परिसर में स्टॉक व मूल्य का प्रदर्शन किया जाए, खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी न की जाए तथा खाद के साथ अन्य उत्पाद लगाकर न बेचे जाएं।

उन्होंने यह बताया कि खरीफ 2025 में विभागीय टीम व रसायन व उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग भारत सरकार द्वारा भी समय-समय खाद विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाता है और जिला में अब तक 19 लाईसेंस निलम्बित किये जा चुके हैं। उन्होंने खाद विक्रेताओं को निर्देश दिये कि रिकार्ड जैसे-बिक्री, स्टॉक व प्रदर्शन में किसी प्रकार की भी कमी पाई जाती है या कोई भी विक्रेता खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी व खाद के साथ अन्य किसी उत्पाद को लगाकर बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि निदेशालय के निदेशानुसार जिन किसानों द्वारा 20-30, 30-40 तथा 40-50 कैटेगरी के अंतर्गत यूरिया बैग खरीदे गये हैं उन सभी का सत्यापन विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि जिला में खरीफ सीजन में लगभग 5 लाख 30 हजार एकड़ में विभिन्न फसलों की कास्त की जाती है, जिसमें लगभग 4 लाख 45 हजार एकड़ में धान की फसल, 42 हजार एकड़ में गन्ना फसल व 38 हजार एकड़ में अन्य दूसरी फसलों की बिजाई की जाती है। इन सभी खरीफ फसलों के लिए जिले में लगभग 95 हजार एम.टी. यूरिया व 20 हजार एम.टी. डी.ए.पी. खाद की आवश्यकता होती है। जिला में अब तक डी.ए.पी. खाद की आपूर्ति लगभग पूरी हो चुकी है तथा यूरिया खाद की 76 हजार एम.टी. की बिक्री की जा चुकी है।

डा. वजीर सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जिला में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और जब भी खाद की नई सप्लाई आती है तो यह खाद विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में बंटवाया जा रहा है और सभी खाद विक्रेताओं की दुकान पर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के फोन नम्बर चस्पा करवा दिये गये हैं। खाद से सम्बधित किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु किसान इन नम्बरों से या सम्बधित खण्ड कृषि अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

प्राकृतिक खेती से ही किसान बनेगा आत्मनिर्भर: संजय कुमार

■ नीलोखेड़ी में पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन, चार राज्यों के अधिकारियों ने लिया भाग

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के तहत विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी में चल रहे प्राकृतिक खेती के विस्तार रणनीतियां विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक संजय कुमार ने की।

निदेशक संजय कुमार ने कहा कि रासायनिक खेती ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया है। इससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में प्राकृतिक खेती ही एकमात्र रास्ता है जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी और धरती को बचाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक डॉ. भरत सिंह घनघस ने बताया कि इस प्रशिक्षण में उत्तर भारत के चार राज्यों के कृषि अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने और लागत घटाने में अत्यंत कारगर सिद्ध हो रही है।

डॉ. घनघस ने बताया कि प्राकृतिक खेती में खाद और कीटनाशकों की जगह किसान अपने संसाधनों-गौमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन, नीम पत्तियों आदि से खेती कर सकता है। इससे न केवल फसल अच्छी होती है बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती से उत्पादों को बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं और यह खेती पर्यावरण हितैषी भी है।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को गुरुकुल कुरुक्षेत्र स्थित प्राकृतिक खेती संस्थान और करोड़ा गांव के किसान मनोज के खेत पर ले जाया गया। वहां उन्हें जमीनी स्तर पर प्राकृतिक खेती के प्रयोगों का अवलोकन करवाया गया।

समापन समारोह में डॉ. सत्यकाम मलिक, डॉ. जसविंदर कौर और डॉ. अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी व प्रशिक्षु उपस्थित रहे। सभी ने प्राकृतिक खेती को ग्रामीण भारत के उज्जवल भविष्य की कुंजी बताया।

परीक्षार्थी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की हिदायतों का पालन करें: डीसी प्रीति

सीईटी परीक्षा के तहत कैथल में लगभग 34 हजार परीक्षार्थी देंगे परीक्षा, बनाए गए हैं 33 परीक्षा केंद्र

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि 26 व 27 जुलाई को हरियाणा में संयुक्त पात्रता (सीईटी) परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सरकार द्वारा परीक्षा को पूरी तरह से नकल रहित व परीक्षार्थियों के लिए सुविधाजनक तरीके से आयोजित करने के लिए तमाम पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सफल आयोजन के लिए प्रत्येक केंद्रों पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। परीक्षार्थियों को आवागमन व ठहरने के लिए जरूरत अनुसार पूर्ण व्यवस्था रहेगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित हिदायतों की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। परीक्षार्थी इस संबंध में जारी हिदायतों का पालन करें।

डीसी प्रीति लघु सचिवालय स्थित वीडियो कांफ्रेंस हॉल में पत्रकारों से बातचीत कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि जिला कैथल में 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 34 हजार परीक्षार्थियों परीक्षा देंगे। यह परीक्षा दो-दो शिफ्टों में प्रातः कालीन व सायं कालीन सत्र में करवाई जाएगी। इन सभी केंद्रों पर कड़ी पुलिस सुरक्षा रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल के प्रयोग को लेकर भी विशेष हिदायतें जारी की जाएंगी। कोई भी स्टाफ सदस्य परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार की नकल व अन्य अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों सहित तमाम सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। परीक्षा की निगरानी राज्य स्तर पर भी की जाएगी। संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारी परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगे। धर्मशालाएं व सामुदायिक केंद्रों को रिजर्व रखा जाएगा, ताकि परीक्षा में लेट होने की स्थिति में परीक्षार्थी की सहमति अनुसार ठहराने की व्यवस्था की जाएगी। जिला में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कोई भी परीक्षार्थी अपनी समस्या दर्ज करवा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम तुरंत समस्या का समाधान करवाएगी। समुचित परीक्षा संचालित हो, इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है।

पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने स्वयं कुछ स्थानों पर निरीक्षण किया है, जहां जन स्वास्थ्य विभाग के नालों की सफाई में कुछ समस्याएं प्रशासन के संज्ञान में आई थी। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम सेवा एक मशीन मंगवाई गई है, जो निरंतर कार्य कर रही है। यह मशीन दिन-रात कार्य कर रही है, जिससे लगभग 200 से 250 फुट प्रतिदिन सफाई की जा रही है। आने वाली बरसात में लोगों को इसमें काफी राहत मिलेगी।

एक अन्य सवाल के जवाब में डीसी ने कहा कि आमजन चाइनीज डोर से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन के संज्ञान में जरूर लाएं। इन मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि घटनाओं के शिकार भी हम होते हैं और प्रयोग भी हम ही कर रहे हैं। इन हानिकारक वस्तुओं से बचें। यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो जिला प्रशासन तुरंत कार्रवाई अमल में लाएगा। इस मौके पर एसडीएम अजय सिंह, डीआईपीआरओ नसीब सिंह सैनी आदि मौजूद रहे।

डीसी प्रीति ने हॉफ मैराथन के सफल आयोजन के लिए जिला वासियों का जताया आभार: डीसी प्रीति ने गत दिनों हुई हॉफ मैराथन के सफल आयोजन के लिए जिला वासियों का आभार जताया और कहा कि जिलावासियों ने उम्मीद से ज्यादा इस आयोजन में भागीदारी की है। हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया है और हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने की दिशा में अच्छा संदेश दिया है। जिला प्रशासन हो, जिले से आमजन हों या फिर जिले में मीडिया है। सभी ने अपने-अपने काम के माध्यम से हॉफ मैराथन को सफल बनाने में सहयोग दिया है। जिसके लिए प्रशासन सभी का आभारी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा ड्रग फ्री हरियाणा का जो संदेश दिया गया है, उसके तहत नशे के खात्मे में सभी सहयोग करें।

'सर्वजन हिताए-सर्वजन सुखाए' ट्रस्ट द्वारा कैथल में जल्द बनाया जाएगा दो एकड़ भूमि में वृद्ध आश्रम

थोड़ी से मेहनत से बदल सकते हैं दूसरों की जिंदगी: ओएसडी प्रभलीन सिंह

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। हरियाणा सरकार में ओएसडी प्रभलीन सिंह ने कहा कि सामाजिक कार्यों में हम सबकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। बुजुर्गों के आश्रय की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि समाज में बदलाव हुआ है और कुछ बुजुर्ग परिवार की उपेक्षा के कारण एकांकी जीवन जीने को मजबूर होते हैं। ऐसी स्थिति में समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना होगा और उन बुजुर्गों के सेवार्थ कार्य करने होंगे। इस दिशा में "सर्वजन हिताए-सर्वजन सुखाए" ट्रस्ट द्वारा कैथल की दो एकड़ भूमि में वृद्ध आश्रम बनाया जाएगा, जिसके लिए जगह की तलाश की जा रही है।

हरियाणा सरकार में ओएसडी प्रभलीन सिंह शुक्रवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में संस्था से संबंधित सदस्यों की बैठक लेकर वृद्ध आश्रम बनाने को लेकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज बदल रहा है और हमें अब इस विषय पर लोगों को जागरूक करना होगा। स्कूल व कॉलेजों में विशेष शिविर लगाने होंगे। बुजुर्गों की सेवा करना बच्चों का कर्तव्य बनता है, लेकिन कुछ बच्चे गलत दिशा में चलकर अपने माता-पिता से दुर्व्यवहार करते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते। ऐसी स्थिति में ही इन वृद्ध आश्रम की आवश्यकता पड़ती है। सर्वजन हिताए-सर्वजन सुखाए ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने जो यह कदम उठाया है, वह काफी सराहनीय है। समाज सेवी संस्थाओं को ऐसे कार्यों में आगे आना चाहिए और जन सेवा करनी चाहिए। इस कार्य में सरकार पूरी मदद करेगी। उन्होंने बैठक में कई ऐसे उदाहरण भी बताए, जिसमें माता-पिता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सी मेहनत से दूसरे की जिंदगी को बदला जा सकता है।

कई ऐसी संस्थाएं हैं, जो जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उन्हें रोजगार तक पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि गुरू तेग बहादुर जी की याद में 350 वां सालां कार्यक्रम को प्रदेश में मनाया जाएगा, जिसके लिए राज्य स्तर पर कमेटी का गठन किया जा चुका है। इसमें लाइट साउंड शो के अलावा अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने समाज सेवा में बेहतरीन कार्य किए हैं और हरियाणा प्रदेश में एक अलग से छाप छोड़ी है।

"सेवा संघ" संस्था के प्रधान शिव शंकर पाहवा व अन्य प्रतिनिधियों ने सबसे पहले ओएसडी प्रभलीन का बैठक में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत किया। प्रधान शिव शंकर पाहवा ने कहा कि प्रो. एसएन मंगला की इच्छा थी कि शहर में दो एकड़ में अच्छा वृद्ध आश्रम बने, जिसमें बुजुर्गों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया हो। यह जिम्मेदारी उन्हें दी थी। साथ ही वे इसके लिए एक राशि का दान कर स्वर्ग सिधार गए। इसी के मद्देनजर "सर्वजन हिताए-सर्वजन सुखाए" के नाम एक संस्था का गठन किया गया। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है और जमीन फाइनल होते ही वृद्ध आश्रम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैथल के काफी लोगों में धार्मिक कार्यों में आस्था रहती है। समाज सेवा में आगे बढ़चढ़ कर कार्य करते हैं। सेवा संघ भी लगभग 45 सालों से समाज सेवा के अंतर्गत निरंतर विभिन्न कार्य कर रही है। इन कार्यों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का काफी सहयोग रहा है।

इस मौके पर अशोक भारती, जरनैल सिंह, कंवल आहूजा, गुरचरण सिंह, सचिन धमीजा, अरविंद कालरा, नवीन मल्होत्रा, प्रवीण ढिल्लो, चंद्र मलिक, दिनेश अरोड़ा, साहब सिंह, सतिंदर भाटिया, प्रशांत आनंद, राजिंदर सिंह, लाड़ी, सतीश सेठ, दीपक अग्रवाल, अजीत सिंह, मंदीप सिंह, सिंदर सिंह आदि मौजूद रहे।

अधिकारी लंबित शिकायतों का जल्द समाधान करें सुनिश्चित: एडीसी

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। एडीसी सोनू भट्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी विभागाध्यक्ष गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की शिकायतें लंबित हैं, सभी संबंधित विभाग लंबित शिकायतों का जल्द समाधान करना सुनिश्चित करें।

एडीसी सोनू भट्ट आज लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ से वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक के उपरांत अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लें और इनका समयबद्ध निपटान करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार से भी औपचारिकता न हो, स्वयं संज्ञान लेकर उस समस्या का समाधान करें। एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भी विभाग की 60 दिन से पुरानी शिकायतें लंबित हैं उनका जल्द समाधान करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान करने के लिए समाधान शिविर जिला मुख्यालय व उपमंडल स्तर पर लगाए जा रहे हैं।

शिविरों के माध्यम से नागरिकों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि वे एक ही स्थान पर अधिकारियों से सीधे संवाद कर सकते है। बैठक में सीटीएम मोनिका, डीडीपीओ संजय टांक, डीआरओ मनीष यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।